THE UNION BUDGET, 2020-21 — *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us resume the Budget discussion. Mr. Navaneethakrishnan, please continue your speech.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I was referring to the aspirational districts and also 'One District, One Product'. I am of the very humble opinion and view that we can create wealth legally by doing agriculture on the basis of the schemes announced by the Central Government in this Budget. I would like to refer to one thing. The Government is going to take comprehensive measures for 100 water-stressed districts. This is a very good move; I welcome it. Another move is chemical-free farming, which alone will bring profit to agriculture. The Government has now taken a decision. From paragraph 23(4) of the Budget speech and also from the newspaper reports, it is very clear that so far, subsidy to the tune of ₹75,000 crores was given to fertilizer companies. Now, it will be stopped and it will be directly disbursed to farmers. The Direct Benefit Transfer (DBT) system will be followed. I also request the Central Government to encourage traditional and natural organic farming by providing incentives. So, the traditional and natural farming must be encouraged. Rightly, our hon. Finance Minister has relied upon the Avvaiyar's poem, 'Bhumi tiruthi Unn', which means, first, 'first tend to till one's land and then eat". If it is not correct, Shri T.K. Rangarajan and Shri Tiruchi Siva will correct it because they may find defect even in translation; that is why, I am saying. I am ready to accept the translation to be given by both of you. So, it is a right move. Because of the excessive use of fertilizers, the soil fertility has been affected. This is the truth. Now, the Government is encouraging the traditional and natural organic farming. Besides, the fertilizer subsidy component will be distributed to the farmers directly. Further, I am very happy that they are going to introduce kissan rail. The agricultural products can be transported by plains. There is such a plan contemplated in this Budget. Further, MNREGA is going to be utilised for fodder development. So, it is a good thing. Fodder development is a very, very important thing because to develop the organic agriculture, we need organic fertilizer, which we can obtain only through cattle farming. So, it is a right move in the right direction to protect the soil fertility. Then, shallow lands can be used for solar plants. By this, at least, about 20,00,000 farmers will be benefitted in this financial year. This is a very good move. So, we are getting very good and clean energy.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

Shallow lands are also going to be utilised profitably. Then, the NABARD is doing good work. There is no doubt about it. As far as Tamil Nadu is concerned, the Branch office or the Regional office is located at Chennai. But every district is having one office, that is, residence-cum-office. There is no specific Government office. So, my humble submission would be, please locate or shift the Chennai office to any part of Tamil Nadu, but not Chennai. Even I myself was not able to find out the office for three years. At last, I found it out and then, I met the officials. I was able to locate the Thanjavur office after making hectic efforts. This office is located in the third floor. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, your time is over.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: One minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kindly remember, before lunch, you had taken six minutes. You were supposed to speak for only four minutes, the time given by your party. So, you are taking your own Party's time. ...*(Interruptions)*... I have no problem. But it will be deducted from your time. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Yes, yes.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, he will finish now.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Yes, I will finish it. I am concluding it. Even I wanted to conclude before lunch.

Sir, there are two things. Tamil Nadu is always a cyclone-prone State. So, my humble submission would be, an institute for climate change must be located in Tamil Nadu.

And also, I understand, subject to correction, that there is only one Government institution for soil sciences at Bhopal. I very humbly and earnestly urge the Central Government to locate yet another Central Government institute for soil sciences in Cauvery-delta region. These are the two requests. And also, the NABARD Office must be shifted and located in the Central part of Tamil Nadu. If it is possible financially? --according to the reports, NABARD is running on profits — they can put up small offices in important districts.

So, I thank the hon. Prime Minister and the Finance Minister. This Budget will definitely help to grow each and every individual citizen, especially, agriculture. We can create the wealth legally. I thank the hon. Prime Minister and the Finance Minister. Thank you, Sir.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आज बजट के ऊपर आदरणीय प्रो. राम गोपाल यादव जी के आशीर्वाद से, आपकी अनुमति से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से ,बजट जैसे विषय पर बड़े-बड़े विद्वान, जैसे चिदम्बरम साहब, साथ ही और भी लोग अपनी बात रख चुके हैं, तो उनको बहुत ही सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उनके बाद substance बहुत कम बचता है, फिर भी जो चीज़ें हम लोगों के ध्यान में आ रही हैं, उन पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। सिर्फ 30 लाख, 42 हजार, 230 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें हमारी वित्त मंत्री साहिबा, हमारी मैडम साहिबा ने बहुत सारे डिटेल्ड प्रावधान किए थे। Aspirational India, Economic Development और caring society का एक नक्शा है। इन्होंने categorize करके काम करने का प्रयास किया है।

सर, हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं। नियम यह है कि दिवाली से एक दिन पहले अपना सारा लेन-देन, जिससे लेना है, देना है, साफ कर लो, उसके बाद चिराग जलाओ, लेकिन सर, हमने यह भी देखा है कि जो बड़े-बड़े कर्जदार होते हैं, जिनका एक-एक बाल कर्ज में डूबा हुआ है, वे सबसे बड़ा पटाखा जलाते हैं। वे दुनिया को दिखाते हैं कि अभी हमारे पास बहुत ताकत बाकी है, तो मुझे कुछ-कुछ ऐसा अहसास हुआ। सर, यह slowdown नहीं है, यह recession है और मुझे लगता है कि सरकार की इमेज को बचाने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उसको mild करने की कोशिश की है कि नहीं, this is a cyclical slowdown, यह फिर रिवाइव हो जाएगा। सर, मेरे पास बहुत से एक्सपट्ट्स के कमेंट्स भी रखे हुए हैं। लोग हताश हैं, उन्हें नहीं लगता है कि इससे रिवाइवल हो सकता है और बड़े-बड़े विद्वान वक्ताओं ने इस बारे में कहा है कि हालात बहुत डिफिकल्ट हैं, हम आपके साथ में हैं, हमें आपसे हमदर्दी है। सच्चाई तो यह है कि आपको जो आलोचना सुननी पड़ रही है, यह गुनाह आपका नहीं था, यह कहीं और हुआ और बातें आपको सुननी पड़ रही हैं। हमें आपसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि हिन्दुस्तान एक आर्थिक आपातकाल की स्थिति में है, सरकार को स्वीकार करना चाहिए और सभी पार्टियों के बीच में बैठकर, जो विद्वान अर्थशास्त्री हैं, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी भी बैठे हुए थे। आपके पास भी अर्थशास्त्री हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उन्होंने लिखी थी, 'RESET.' मतलब fantastic. मुझे लगता है कि सच से दूर भागने वाला चश्मा होता है। मुझे लगता है कि एक ऐसा भी चश्मा है, जो हमको सच्चाई से दूर ले जाता है। वह चश्मा यह बजट स्पीच तो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है।

सर, यह जो पॉलिसी शॉक हुआ है, इसके बारे में कई वक्ताओं ने कहा है। Demonetization और compulsive digitalization ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिन्होंने आज हमें यहाँ लाकर पहुँचा दिया

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

है। पहले भी दुनिया भर में मंदी आई थी, लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ा था। सर, हिन्दुस्तान में खेती non-taxable होती थी और यह भी सच है कि 67 परसेंट से भी ज्यादा लोग खेती से जुड़े हुए थे, उनको harass करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन, एक जो माइंडसेट बना हुआ था, पता नहीं कहाँ से यह विचार आया था कि कहीं न कहीं उन लोगों के पास सारा ब्लैक मनी रखा हुआ है, जो खेती कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं या जो हाउस वाइव्स हैं। वह सारा ब्लैक मनी निकाल दिया गया और आज हालत यह है कि देश खाली है।

सर, जो ख़बरें आ रही हैं, वे बड़ी खतरनाक हैं। ऐसी ख़बर आ रही है कि एक प्रतिशत आबादी के हाथ में 73 प्रतिशत वेल्थ जा चुकी है। यह बड़ी खतरनाक बात है! आपके आगे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। जो एक प्रतिशत आबादी है, ये वही लोग हैं, जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को वेल्थ में कन्वर्ट किया है और आज हालत यह है कि उनके हाथ में पूँजी नहीं है। जब उनके हाथ में पूँजी नहीं है, उनकी आमदनी खत्म हो गई, उनके रिसोर्सेज़ खत्म हो गए, तो खपत कहाँ से बढ़ जाएगी? आज आपकी सबसे बड़ी चिन्ता यही है कि जो भी औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, उसकी खपत बढ़नी चाहिए। सर, जब आदमी के पास पैसा ही नहीं रह गया है, तो वह कहाँ से खपत बढ़ाएगा? आज ये सवाल पैदा हो रहे हैं। यह सभी लोगों ने कहा भी है। जितने विद्वान वक्ता हैं, वे सब यही कह रहे हैं कि कुछ भी करिए, समाधान वहीं से निकलेगा, जब लोगों की purchasing power दोबारा बढ़नी शुरू होगी। शिक्षा पर, खाने पर, कपड़ों पर, टेलीकम्युनिकेशन पर, ट्रैवल पर, स्कूलिंग पर, हर चीज़ पर लोगों का खर्चा है। मैंने एक लिस्ट तैयार की थी, जिसके अनुसार ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, जिनकी जरूरत आदमी को रोज पड़ती है, लेकिन आदमी ने compromise कर लिया है। आज ही इस बात का जिक्र हो रहा था। चिदम्बरम साहब बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खपत का लेवल 10 परसेंट डाउन हुआ है। यह तो खतरे की घंटी है! अगर हम इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रहना चाहेंगे, तो धोखा हो जाएगा।

सर, इस देश की आबादी लगभग 130 करोड़ क्रॉस कर रही है, जिसमें 85 परसेंट आबादी नौजवानों की है, जिन्हें काम चाहिए, जिन्हें रोज़गार चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपने इस बात पर ग़ौर किया कि 85 परसेंट नौजवान critical mass होता है। यह एक बहुत बड़ी आबादी हुई। अगर आप उसकी आवश्यकताओं को ऐड्रेस नहीं कर पाएँगे या उन रास्तों पर नहीं चल पाएँगे, जिनसे उन लोगों की आवश्यकताएँ ऐड्रेस होंगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है।

सर, मेरी चिन्ता इसलिए भी है, क्योंकि मुझे Mr. David Rockfeller का बयान पढ़ने को मिला, जो दुनिया के बहुत बड़े बैंकर हैं। वे बैंकर ही नहीं, बल्कि बैंकों के पितामह हैं। उनका कहना है, "We are on the verge of global transformation. All we need is the right major crisis and nations will accept a new world order." यह new world order क्या है? जो new

colonial system होता है, यह वही है। आज इन लोगों ने हिन्दुस्तान पर 70 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कर्जा मढ़ दिया, हम उनसे बड़ी खुशी-खुशी कर्जा लेते रहे और आज हालत यह है कि वे हमारी पॉलिसी बदल रहे हैं और एक crisis का इंतजार कर रहे हैं, जो crisis हम बनाकर उनको देने वाले हैं, जिससे नया world order set हो। यह नया world order किसानों की बात नहीं करता, यह मज़दूरों की बात भी नहीं करता, यह नौजवानों की बात भी नहीं करता, यह सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की बात करता है। दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े बैंकर्स हैं, वे किसी भी देश के मजबूत बैंक को बर्दाश्त नहीं करते। वे कठपुतली सरकारें बनाते हैं और उसके बाद वे ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, ताकि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम collapse हो और उसके बाद पूरा बाजार उनके लिए खुल जाए। सर, पूरी दुनिया में खनिजों के लिए लड़ाई चल रही है और हिन्दुस्तान उसका शिकार हो चुका है। अभी-अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि कोयले का open auetion होगा। हम सिर्फ royalty पर ज़िन्दा रहेंगे या उस कोयले का कभी इस्तेमाल भी करना जानेंगे यह सवाल सिर्फ कोयले पर ही नहीं है, बल्कि सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज़ और पूरी धरती पर जहां कहीं मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, वे इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिकार हो रहे हैं और वहां की सरकारें, जो चुनकर बनी हुई सरकारें हैं, वे कर्ज में बंधी हैं, बाध्य हैं, जो वे चाहें वह करने के लिए। हमारे लोग लाचार, मजबूर, गरीब और बेसहारा, जो सरकार के सहारे हैं, उनमें यह धोखा बना हुआ है कि वे सरकार के सहारे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ने उनसे अपना पल्ला छुड़ा लिया है।

महोदय, यहां सबका साथ, सबका विकास की बात हो रही थी। हिन्दुस्तान में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की आबादी 16.6 परसेंट है, उनके लिए डेडिकेटेड बजट का आवंटन 2.73 परसेंट है, आप मज़े की बात देखिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की आबादी 8.9 परसेंट है, उनके लिए डेडिकेटेड बजट 1.76 परसेंट है, माइनॉरिटीज़ की population 20 परसेंट है, उनके लिए डेडिकेटेड बजट 0.16 परसेंट है, ओबीसी और बैकवर्ड की population 43 percent है, उनके लिए डेडिकेटेड बजट 0.07 परसेंट है और others की आबादी 11.8 परसेंट है, उनके लिए बजट का डेडिकेशन 95.28 परसेंट है। सारा राज़ खुल गया न।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान): बाकी योजनाएं भी होंगी।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आप भेजेंगे, लेकिन मैं केवल यह बताना चाहता हूं...

श्री उपसभापति: वर्मा जी, आप चेयर को address कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, बड़ी मज़ेदार बात है कि लोकप्रिय सरकार है, 36 परसेंट वोट पाकर जीती हुई सरकार है, लेकिन जो उनके बजटरी कमिटमेंट्स हैं, उनमें कोई धोखा नहीं है ...**(व्यवधान)**... सर, ये वे लोग हैं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, ये वे लोग हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान के अंदर wealth generation में अपनी जान लगायी है।

श्री उपसभापतिः कृपया आपस में बात न करें।

श्री रवि प्रकाश वर्माः महोदय, ये वे लोग हैं, जिन्होंने इस देश को हिन्दुस्तान बनाया है। महोदय, जो गरीब और अमीर के बीच में गैप बढ़ रहा है, यह खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। मैं सिफ आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आपने जो 95.28 परसेंट बजट ऐलोकेशन किया है, इस पर आप विचार कीजिएगा। आज यही लोग हैं, जो हिन्दुस्तान की सोसायटी के marginalize section हैं, यही लोग आज इस अर्थव्यवस्था को बाहर निकालेंगे। कया आपने स्माल सेविंग्स की पावर को कभी जाना? उस दिन चिट फंड कंपनियों की जब चर्चा चल रही थी तो यह बात सामने आयी थी कि चिट फंड कंपनियों में जिन लोगों का पैसा मारा गया, वे गरीब लोग हैं, लाचार किसान, गृहिणियां, छोटे काम करने वाले लोग, नौकरियां करने वाले लोग हैं। कितनी रकम थी, वह रकम 3 लाख करोड़ रुपये थी। यह जो small savings की power है, वह आपको दिखाई नहीं दी। मुझे हैरत लगती है कि आप अगर इस देश से खुलकर कहते, शास्त्री जी की तरह सामने आते और कहते कि हम एक crisis के बीच में खड़े हैं, देशवासियों, हमारी मदद करो, फिर आप देखते कि उसके बाद हिन्दुस्तान के अंदर क्या होता। महोदय, जो सबका साथ, सबका विकास था, वह आईना सामने दिखायी पड़ रहा है कि किसका कितना विकास है? उसमें कोई धोखा नहीं है।

महोदय, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पूरी दुनिया का एक टारगेट है, हम भी उसके शिकार हुए हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का लक्ष्य क्या है, वह है सस्ता लेबर। यह सच्चाई है कि आज की तारीख में हिन्दुस्तान जिस crisis में फंसा हुआ है, उसका इलाज यही है कि लेबर जितना insecure हो जाएगा... दिल्ली शहर में तीन सौ रुपये दिहाड़ी चलती है, कैसे भी अगर यह हो जाए कि दिहाड़ी 50 रुपये रोज़ हो जाए तो अर्थव्यवस्था जिन्दा हो जाएगी, काम करने लगेगी, सारे के सारे उपक्रम मुनाफे की ओर चलने लगेंगे। क्या यही समाधान तो नहीं है?

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ईज़ ऑफ लिविंग की बात भी कर रहे थे। हम लोग भुखमरी के पायदान पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, भूखा आदमी, ईज ऑफ लिविंग और फिट इंडिया को साथ-साथ रखकर देखने से बहुत मज़ा आता है। फिट इंडिया कार्यक्रम, भुखमरी कार्यक्रम और nutrition का लेवल, गज़ब है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप एक काम क?यों नहीं करते, खबर लगी है कि 1 प्रतिशत आबादी के पास 73 परसेंट wealth है। आप उस wealth पर टैक्स लगाइए, आपक 7 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। आपको मालूम है, 7 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। उनको exemption क्यों है? इस पैसे की जरूरत गरीबों को, लाचारों को और मजबूरों को थी। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय कम है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)** *पीठासीन हुईं*]

मैडम, हिंदुस्तान में 80 परसेंट आबादी caste-based shackles हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो जातिगत ढांचा है, यह lock-in-system है। यह आदमी की इकोनॉमी

को भी लॉक करता है, उसकी पोलिटिक्स को भी लॉक करता है और सामाजिक रूप से तो लॉकिंग है ही। इतने प्रबल समर्थन के बाद इसकी अनलॉकिंग क्यों नहीं होती है? कायदे से तो यही लोग अगर अनलॉक हो जाएंगे, इस जाति के बंधन से बाहर आ जाएंगे, तो productivity देखिएगा। यदि कोई आदमी 200 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, तो मेहनत करते-करते उसकी दिहाड़ी 2,000 रुपये हो जाएगी। महोदया, मेहनत manual job, menial job - और खाली बैठे-बैठे, तिकड़म से, खाली पॉलिसीज़ बनाकर, खाली नई इन्वेस्टमेंट करके और खाली होशियारी करके करोड़पति, अरबपति बनना इस देश में बाएं हाथ का खेल है। सर, हालांकि चीज़ें बहुत थीं, लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं और मेरे बाद दो वक्ता और हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, जो agriculture job creation है, वह specific zone है और वहीं से रास्ता निकलेगा। महोदया, जो crop rotation की planning है, soil quality का management है, crop protection का कारोबार है, ये सब skilled job हैं। जो organic crops का कारोबार है, post-harvest के मामले हैं, food processing technologies हैं, seed certification और production का काम है, online marketing के skills हैं, agricultural और engineering के मामले हैं, agri-business administration है, export का काम है, capacity building है। मैडम, ये वे कैरियर हैं, जिन पर इन्वेस्ट करने से आपका फ्यूचर दुरुस्त रहेगा। गांव के अंदर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की इकाई बनाकर काम करेंगे, तो आपका खजाना भर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। महोदया, संपत्तियां बेचकर काम चल रहा है, जैसा कि हमारे साथियों ने जिक्र किया। यह विकास नहीं, विनाश होता है। एक चीज़ और भी है, स्थायी रूप से हिंदुस्तान में जो युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, मैं अभी देख रहा था कि आज ही एक सवाल का जवाब मुझे दिया गया। डिफेंस फोर्सेज़ पर जो allotment था, वह पूरा नहीं हो पाया। वहां फौजों में हमारे बच्चे हैं। वहां बड़े-बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं। जो इस देश के कामगार लोग हैं, वर्किंग क्लॉस है, उनके बच्चे हैं और उनके लिए सिक्योरिटी थी कि नौकरियां मिल जाती हैं। अब चूंकि पेंशन के सवाल पैदा होने लगे हैं, रकम बढ़ गई है पेंशन की, liability बढ़ गयी है, जो आवंटन थे, उसमें पिछले साल में ही 31,882.95 करोड़ का deficit था। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): आपका एक मिनट ही बचा है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं क्लोज़ कर रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, चूंकि समय का बड़ा बंधन है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हेल्थ के ऊपर आपने जी.डी.पी. का जो 2.3% खर्चा किया है, उसको 5% कीजिए। यह स्वच्छता कार्यक्रम जो बनाया गया है, जो 10 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, उनमें soak pit बना है और soak pit आपका हेल्थ बर्डन बढ़ाने वाला है। सर, रेलों में बॉयो-टॉयलेट्स लग रहे हैं और गांवों में जो 11 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, उनके अंदर soak pit बन रहा है। इससे सीधे-सीधे यह पता लगता है कि जो दवाई कंपनियां हैं, उनकी लॉबी मंत्रालय के अंदर काम कर रही है। यह आपका हेल्थ बर्डन बढ़ाने वाली है। जरा इस पर गौर करिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): रवि जी, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदया, सिर्फ एक मिनट का समय और दीजिए। मैं हेल्थ पर एक चीज़ और कहना चाहता हूं। आप खर्चा बढ़ाइए, चूंकि जो चाइना में चल रहा है, वह खेल नहीं है और वह बड़ी बात है। वर्ष 2011 में हॉलीवुड से एक मूवी Contagion आई थी। उसके अंदर यह ईवेंट पूरा का पूरा दिखाया गया था। यह एपिसोड वर्ष 2011 में पूरी दुनिया ने देखा है और वह अब दोहराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए यह बहुत माकूल टूल है? ...(**समय की घंटी**)... अगर आपके health expenditure नहीं बढ़े, तो सब कुछ करने के बाद भी आप हार जाएंगे। ...(**समय की घंटी**)... महोदया, मैं महिलाओं के बारे में एक चीज़ कहना चाह रहा था। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन): रवि जी, आपकी पार्टी से जो वक्त मुक़र्रर है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदया, मैं बस क्लोज़ कर रहा हूं।

प्रो. राम गोपाल यादव: बाद वाले वक्ता अपना समय कम कर देंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि वह हमारी आबादी है। उनकी जो सर्विसेज़ फैमिली के लिए हैं, वे unpaid services हैं। उनको 6 घंटे, 7 घंटे अपने घर में व्यतीत करने पड़ते हैं। क्या आप उनकी इन सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन कर पाएंगे, उनको जी.डी.पी. में कहीं attach कर पाएंगे? यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर पाए, तो आप महिलाओं के साथ बहुत न्याय करेंगे। मैडम, इस बजट के संबंध में मेरा अनुमान था कि हम समय के इस मोड़ पर हैं कि यह mother and child focused, child friendly बजट होता। हमारी जो नयी पीढ़ी है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, इन्हीं पर हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं, यही लोग भारत हैं, हिन्दुस्तान हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इन पर investment करेंगे तो आप उस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी मेहनत कामयाब हो, आपके संघर्ष कामयाब हों और हिन्दुस्तान इस अंधेरे से बाहर निकले। हम सब लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं - आप हाथ तो बढ़ाइए, यह पूरा देश आपका इंतज़ार कर रहा है, धन्यवाद।

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Madam, after this Budget was presented in the Parliament, my hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, had given his reactions, which I would like to quote. He said, "We welcome the following initiatives - Krishi Rail and Krishi Udan for a seamless national cold supply chain; PM-KUSUM to cover 20 lakh farmers for solar pumps; and, removal of Dividend Distribution Tax and introduction of concessional component tax. Odisha had requested for extension of concessional tax rates to cooperatives in line with corporate tax cuts. We welcome the announcement of concessional tax rates for cooperatives and increase of deposit insurance coverage from ₹ 1 lakh to ₹ 5 lakh, announcement for new Education Policy and FDI in the education sector."

The Indian economy was plagued by one of the slowest growth rates and the highest unemployment in the last many decades, coupled with a slowing world economy, rising protectionism, including the U.S.-China trade war and Brexit, it was one of the most challenging times to present a Budget. Expectations amongst people were high from the Government to present a big bang Budget to kick-start the economy by pushing domestic consumption and investment cycle in the economy. The Budget has, however, come with several incremental measures for various sections of the society. As termed by the Finance Minister, it is *"jan jan ka Budget"* and which, in aggregate, would provide necessary impetus to the economy. The Government has been very clear that it was not willing to bridge the fiscal deficit target by contravening the FRBM Act, 2003, and thereby with falling tax revenues, perhaps, the Government had only so much leg room. On the tax front, therefore, there is very little in the Budget in terms of simplification, but a lot on widening the tax base and increasing the compliance burden on the taxpayer. Hitherto, sale and purchase of goods was outside the ambit of any tax deduction at source (TDS) or tax collection at source (TCS). The Finance Bill now proposes to levy a TCS of 0.1 per cent whereby the seller, whose sales/turnover in the preceding year exceeds ₹10 crores, would collect the aforesaid tax from the buyer during the financial year on sale of goods in excess of ₹50 lakhs in a year. Another proposal to make the TCS net wider is the proposed levy of TCS at the rate of 5 per cent on remittances sent abroad under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) and on sale of overseas tour packages by tour operators. The proposal to collect tax on LRS is particularly harsh and needs to be revisited. This also adds to the compliance burden as another return would have to be filed by the person collecting the tax.

The Finance Minister, like a seasoned leg spin bowler, has thrown a googly by proposing an amendment to change determination of residential status of Indian citizens staying abroad. Though the intention of the Government is to tax stateless persons, but the language of the proposed section and that of the latter Press Release have confused us as to what the Government is intending to tax. Also, reducing the number of days of stay in India from 182 to 120 days for Indian citizens living abroad is not a good step. The proposal regarding e-appeal and e-penalty seems to be a pre-mature step. After the stabilization of e-assessment or faceless assessment proceedings, the Government could have thought of moving to next step of e-appeal and e-penalty. In the appellate proceedings, the tax payer wants to be heard and wants to make the

[Shri Prashnta Nanda]

authorities understand his stand, which is not possible in a faceless scenario. In terms of the misses, the most important point seems to be rationalisation of Long Term Capital Gains tax. In our view, there was a need to remove Long Term Capital Gains tax on shares and reduce the tax rate of Long Term Capital Gains on the sale of immovable property. Any reduction in this rate would only lead to higher inflow of money in the formal economy and discourage transactions outside the books. It should be remembered that the intent to evade tax goes hand-in-hand with the high tax rate, and, therefore, there is a need to reduce the rate on sale of immovable property. We hope the Government will consider this in the next year's Budget.

Madam, some years back, there was an economic depression throughout the world, mostly in Europe. It could not affect our country so much because our rural economy was very, very strong. It would have been much better had some more money been infused for MNREGA works. The labour laws should have been amended and the wages which the labour gets should have been enhanced. We are talking of doubling the farmers' income. Do you think the farmers' income will double if the farmer continues with the same traditional crops of paddy and wheat? No. He has to go in for floriculture, he has to go in for horticulture and he has to go in for cash crops. Madam, it would have been better if you could increase the money or help which the farmer is getting now.

As far as my State is concerned, through you, I would like to make some requests to the hon. Minister. With regard to the clean energy cess, we want, at least, some sharing with States for specific use in places where the cess is raised to do clean energy activities. Prudence in financial management should not be a negative factor in fund allocation by Finance Commission. In fact, the Finance Commission should reward the States who have managed the State finances better. Royalty on coal needs revision. Regarding archaeological sites, Odisha should not be left out. It has maximum sites. We should have a National Tribal Museum in Odisha. This is my request.

It should be a special focus State to take care of recurring calamities. It breaks the financial backbone of the State. Although, I definitely thank the hon. Minister for the help which was provided to the State of Odisha at the time of cyclone Fani and other calamities, I request that any State which faces major disasters should be given,

special focus for three years for recovery and reconstruction, and, in terms of 90:10 per cent for Central schemes, a tax holiday etc. Please speed up the railway projects where the State is providing free land and 50 per cent cost of construction; Odisha is one of the very few States which does this. ...*(Time-bell rings)*... Teledensity and banking density both have to be increased. Also, drinking water needs focus. I do not have to go for a longer speech. I hope the hon. Minister will definitely take care of the request which I have made for my State. The most important thing is that more stress should be given on farmers and rural economy. I hope she will definitely take some action in this matter. Thank you very much.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): धन्यवाद, वाइस-चेयरमैन महोदया। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है ,वह विकासोन्मुख है ,ग्रोथ ओरियंटेड है। मैं भारत के पूर्व वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था ,उन्होंने इस हाउस में 9 बजट प्रेज़ेन्ट किए हैं। मोरारजी देसाई जी के बाद उनका दूसरा नम्बर है ,लेकिन अंत में, जो वे कह रहे थे ,तो वह मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वे क्लास की और मास की चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि जो संसाधन हैं ,जो पैसे हमारे वित्त में हैं ,वे मासेज़ के पास जाने चाहिए ,क्लासेज़ के पास नहीं। तो क्लास और मास की बात तो समझ में आती है ,चूंकि वे खुद भी Harvard में पढ़े हैं ,तो वह क्लास है न, कोई मास तो है नहीं।

श्रीमती जया बच्चन: यह जरूरी नहीं है।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: यह जरूरी है। देखिए, हम लोग तो जेएनयू में पढ़े हैं, हमारी वित्त मंत्री जी भी पढ़ी हैं, इसलिए हम लोग तो मास वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप बात कर रहे हैं क्लास की और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे थे कि किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने सिर्फ 54,000 करोड़ रुपये दिए। आप जरा समझिए ,आपने तो एक रुपया नहीं दिया था, तो कम से कम हम लोग कहां पहुंचे हैं! हम ज़ीरो से 54,000 करोड़ पर पहुंचे हैं और आगे और पहुंचेंगे। आप क्या कह रहे थे? ...**(व्यवधान)**... आप कह रहे थे, आप यह भी जरा जान लीजिए। वे क्या कह रहे थे, वे मास की बात कर रहे थे। पूरा का पूरा यह हमारा जो एससी और ओबीसी का बजट है ,उस बजट में 85,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है, वह किस क्लास को जाएगा! हमारा जो एसटी है, उसके लिए 53,600 करोड़ रुपया दिया गया है, वह किस क्लास को जाएगा, क्या वह मास नहीं है? हमारे जो दिव्यांग हैं, जिनको 9,000 करोड़ रुपये जाएंगे ,वे मास हैं या क्लास हैं? हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का बजट देख लीजिए, जो कि 1.60 लाख करोड़ का है ,वह कहां जाएगा? ग्रामीण विकास के लिए जो 4.23 लाख करोड़ है ,ज़नाब, वह कहां जाएगा? इतना ही नहीं ,आपको चिंता किसकी है? यहां चिंता इस बात की है कि गरीब के घर में नल का जल पहुंचे और उसके लिए अगले पांच सालों के लिए 3 लाख 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह किसके घर में जाएगा? इसलिए आप मास और क्लास की बात मत करिए। यह सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए काम करने के

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

लिए ही है। आप ज़रा इस चीज़ को देखिए। आपको सबसे पहले किसानों को इस बात के धन्यवाद देना चाहिए ,जो आपने अभी तक नहीं दिया है। पहली बार इस देश में हमारा जो पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है, वह 311 मिलियन टन हुआ है। यह किसने किया था? यह उसी किसान ने किया और इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पूरा का पूरा एग्रील्कचर का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, इसमें क्या फायदा हुआ है? इससे लोगों को न सिर्फ केवल रोजगार मिला, बल्कि जो हमारे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनका nutritional level भी बढ़ा है। पहले क्या होता था? वे रोटी खाते थे, तो दाल नहीं होती थी, वे रोटी खाते थे, तो सब्जी नहीं होती थी और नॉन-वेज की बात तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आज वे कह रहे थे और अभी हमारे वर्मा जी भी बोल रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में consumption 10 प्रतिशत नीचे चला गया है। वर्मा जी और पूर्व वित्त मंत्री जी ,जो चले गए ,आप लोग तो नहीं जाते हैं ,मैं गांव में ही रहता हूं और मैं अपने गांव में देख रहा हूं कि पहले लोग जितना खर्च करते थे और खाते थे ,उससे ज्यादा कर रहे हैं। मेरा गांव बिहार में है ,कोई बाहर नहीं है और आप क्लास और मास की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि इस बजट में nutrition level को बढ़ाने के लिए 35,600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इससे किसका nutritional level बढ़ेगा? महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिए, महिलाओं के लिए यह व्यवस्था है, यह पूरा का पूरा बजट कहां जाएगा और किन के लिए होगा, यह पूरा का पूरा बजट महिलाओं के लिए है। इसलिए आप ऐसी मानसिकता से उबरिए।

महोदया, आप जिसे tax terrorism कह रहे थे, वह क्या है, मैं उस बारे में बताना चाहता हूं कि लोगों की एक सोच यह है कि बहुत सारे जो सिविल कानून हैं, उनमें civil liability आ गई है और इससे लोग घबराए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप बजट में पढ़िए, मैं फिर वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसकी पूरी की पूरी एक study की जा रही है, जो Company Law है या जो और laws हैं, उन सभी को ठीक से analyze किया जाए, जिससे कि लोगों के मन में किसी भी प्रकार का भय न रहे और वे निर्भय होकर अपना business करें और अपना व्यापार करें, लेकिन अगर गलत काम करेंगे, तो कहां जाएंगे ? गलत काम करने वालों की जगह एक ही है। इसलिए मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

महोदया, वित्त मंत्री जी को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने एक और कानून की चर्चा की और वह खासकर के महिला सशकतीकरण के लिए है। हमारी लड़कियों की marriage की जो age है, वह वर्ष 1978 में 8 वर्ष हुई थी। आज आप देखिए, उन्हें जिस प्रकार के अवसर मिले हैं, उनसे उन्होंने बहुत तरक्की की है। निश्चित रूप से जो MMR Vaccine की dose की बात है, उसे भी ठीक करना चाहिए। Nutrition level भी ठीक करना चाहिए। मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसमें भी एक task force बनाने की बात कही

है और जब उसकी रिपोर्ट आएगी, तो उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो बच्चियां हैं, उनकी जिस एज में शादी होती है, उस पर विचार होना चाहिए। इसके लिए भी आपने एक कमेटी बनाई है, यह भी एक अच्छी सोच है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ।

महोदया, आप कहेंगे कि बजट में क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि बजट में सिर्फ और सिर्फ चर्चा किस की है, वह सिर्फ ग्रामीण इलाके की चर्चा की गई है। आप सब जानते हैं कि हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में कहां से कहां जा रहा है। अभी ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि हमारे देश में बिजली की कम खपत हो रही है। देखिए, मैं तो बिहार का हूं। बिहार में एक समय, मैं year का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यदि मैं year का नाम लूंगा, तो कुछ लोगों को खराब लगेगा, उस year में मात्र 450 से 500 मेगावॉट की खपत होती थी, लेकिन आज उसी बिहार में 5000 मेगावॉट से ज्यादा खपत हो रही है। बिजली की खपत कहां कम है? मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और उनकी बगल में रेल मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आज हम जिस सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसके अन्तर्गत हमें पूरी की पूरी ऊर्जा सूरज से मिलनी है, जो हमारी टिकाऊ एनर्जी होगी। आप रेलवे ट्रैक के आसपास की पूरी की पूरी जमीन को सोलर ऊर्जा के लिए उपयोग करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने इसमें किसानों को भी लिया है। आपने क्या कहा- किसानों की जो fallow land है, जिस पर वे खेती नहीं करते हैं, उस पर भी वे सोलर प्लांट लगाकर, 'अन्नदाता' के साथ-साथ 'ऊर्जादाता' बनने जा रहे हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं।

महोदया, इस संबंध में, वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि बिहार में और खासकर हमारे northern बिहार में, बहुत सारी हमारी water bodies हैं और बहुत बड़ी-बड़ी bodies हैं। उनके बारे में study भी हुई है कि किस प्रकार से वहां पर सोलर ऊर्जा का काम किया जाए, जिससे कि उसके नीचे मछली-पालन भी हो जाए और हमारे यहां जो मखाने की खेती होती है, उसका भी, यानी मखाने का पालन भी हो जाए और उसके ऊपर हम कैसे सोलर प्लांट लगाएंगे, इस बारे में भी वे ध्यान रखें। इसलिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार से काम करने से जो हमारे किसान हैं, निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी।

महोदया, मैं एक दूसरी और चीज के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, हालांकि उस बारे में सिर्फ दो ही लाइनें बजट में लिखी हैं, लेकिन उसमें बहुत गहराई छिपी हुई है। यह पूरा का पूरा जो inlandwater way-1 है, जिसमें हमारा बिहार आता है और वह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, उसके दोनों किनारों पर आपने "अर्थ-गंगा प्रोजेक्ट" बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीया वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। यह कोई साधारण सोच नहीं है। यह पूरा का पूरा हमारा इलाका है, वह वर्जिन इलाका है, जिसके दोनों बैंक्स पर आगे चलकर economic activities होंगी। इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये economic activities इस प्रकार से हों, जिससे कि हमारा environmental degradation भी न हो। आप इस बात को देखिए और समझिए कि इससे विकास के कितने अवसर मिलेंगे।

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

महोदया, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार में NDA की सरकार है। आप सब लोग गया और राजगीर के बारे में भी जानते हैं। दुर्भाग्य से उस इलाके में पानी की कमी रहती है। हमारी NDA की सरकार, जिसके नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्हें मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि उनकी सरकार पहली बार बिहार में गंगा का जल गया पहुंचाने जा रही है, यह साधारण बात नहीं है। उस सरकार की यह सोच है। आप जब गया जाएंगे, तो आपको गंगा जल मिलेगा। आप तो जानते ही हैं गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए भी जाते हैं। वहां आपको गंगा का जल मिलेगा। इस प्रकार देखिए हमारी NDA की सरकार बिहार में क्या कर रही है और इससे कितनी संभावनाएं बनती हैं।

महोदया, मैं एक और बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और वह यह है कि टमाटर, प्याज और आलू, ये तीनों, जब ये पैदा किए जाते हैं, तो हमेशा उनकी कीमतें बहुत कम रहती हैं। जिस समय इनका उत्पादन होता है, उसके 4-5 महीने के बाद इनका रेट बहुत बढ़ जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने न सिर्फ जो पूरी की पूरी हमारी storage की व्यवस्था है, उसको line-up किया है, बल्कि आप इसमें रेलवे को भी लाई हैं, civil aviation को भी लाई हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने गाँवों में भी storage बनाने के लिए वहाँ हमारे जो Self-Help Groups हैं, उनको भी इसमें जोड़ा है। यह साधारण बात नहीं है। आपने अपने बजट में कहा है कि आज इस देश में 58 लाख Self-Help Groups हैं, मतलब करीब-करीब 6 करोड़ 60 लाख लोग हमारी जीविका से जुड़े हुए हैं। बिहार में हमारे 9.5 लाख Self-Help Groups हैं और इनमें करीब-करीब 1 करोड़ लोग पहुँचने जा रहे हैं। आज आप जान लीजिए कि यह साधारण उपलब्धि नहीं है। जो महिलाएँ हमारे गाँवों में रहती थीं, आज वे बैंकों में जाती हैं, बैंकों से deal करती हैं और पूरी की पूरी economic activity बढ़ रही है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। इससे महिलाओं का empowerment हुआ है। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खास कर आगे आने वाले समय में जो महिला entrepreneurship है, उसकी संख्या बढ़ेगी और इससे हमारे देश को फायदा होगा।

आपने रेलवे में एक और अच्छा काम किया है। आपने एक अच्छा काम यह भी किया है कि पहली बार जो पूरा का पूरा रेलवे है, रामविलास बाबू भी रेल मंत्री रहे हैं, वे अभी भी मंत्री हैं, उसमें पूरा का पूरा departmentalism चलता था, उसमें इसको दूर किया है। वे ठीक कह रहे थे कि अगर कोई accident होता था, तो मेम्बर पहले पता करते थे कि इसमें किसकी गलती है, यह engineering का failure है signal का failure है या traffic का failure है। लोग इसी में लगे रहते थे। लेकिन आपने यह पूरी की पूरी जो कार्रवाई की है, इसमें आप एक Integrated Railway Management Service बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। इससे पूरे set up में एकता आएगी और इससे हमारे railway का जो network है, वह आगे और भी बढ़िया तरीके से काम कर पाएगा। रेलवे में आज की तारीख में खास कर

इसकी आवश्यकता है कि जहाँ-जहाँ हमारे जो बहुत पुराने projects पड़े हुए हैं, उन projects को एक बार आप जरूर देख लीजिए, जिसका Rate of Return (ROR) अच्छा है। जिसका ROR 14-15 से ऊपर है, अगर उसको हम लोग privatize कर देंगे, तो निश्चित रूप से उससे transportation में भी फायदा होगा और public का जो traffic है, वह भी बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको एक project का नाम देना चाहूँगा, खास कर हमारे पटना के लिए जो third line बनने की बात है, वह है शेखपुरा से नेऊरा लाइन। उसमें दनियावां से बिहार शरीफ तक पूरी लाइन शुरू हो चुकी है और उस पर ट्रेन चल रही है, लेकिन बाकी में काम बचा हुआ है। अगर आप उसको पूरा कर देंगे, तो आपको पटना के बाहर एक third line मिल जाएगी और उससे हम लोगों को काफी फायदा होगा।

वित्त मंत्री जी, मैं एक और बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। पहली बार आपने हमारे heritage और culture के बारे में जो सोचा है, उसके चलते आप एक Indian Institute of Heritage and Conservation खोलने जा रही हैं। हमारे बिहार में human resource है, water resource है और पूरा का पूरा heritage है। अगर आप दुनिया का इतिहास देखेंगी, तो उसमें बिहार का इतिहास एक खास स्थान रखता है। आप जानती हैं कि वहाँ Cyclopean Wall है। दुनिया में यह Cyclopean Wall या तो ग्रीस में है या हमारे बिहार के राजगीर में है। उस जमाने में यह Cyclopean Wall, इसकी बड़ी-बड़ी दीवारें करीब 27 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर बनाई गई हैं। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय नीतीश बाबू ने उसको UNESCO site घोषित करने के लिए लिखा है। आप जानती हैं कि बिहार में हमारी ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जिनको हम पूरा का पूरा pre-historic काल का कहते हैं। हमारे रामविलास बाबू बैठे हुए हैं। इनमें चेचर है, यह बहुत पुराना है, फिर चिरांद है, यह pre-historic site है। अगर आप पूरे के पूरे Mauryan period, Magadh period को देखिएगा, तो ऐसी बहुत सारी sites हैं। आप नालंदा यूनिवर्सिटी को देखिए। नालंदा है, विक्रमशिला है, ओदंतपुरी है। तिलहारा में एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हमारे Nobel Laureate गए थे। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि तिलहारा में खुदाई हुई थी , यह वहाँ चौथी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन 5 साल से इसका काम बंद है। हमें इसको देखना चाहिए। मेरा अनुरोध होगा कि आप जो institute खोलने जा रही हैं, इस institute को आप बिहार में खोलिए। अगर जरूरत समझें, तो जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, उसके बगल में खोलिएगा, तो इससे आपको फायदा होगा। इससे वहाँ इन चीजों की पढ़ाई होगी और इसको फायदा मिलेगा। आज आप जानते हैं कि हमारे पूरे के पूरे देश में लोग museum में जाते हैं, तो वहाँ ठीक से लोग बता नहीं पाते हैं, archaeology के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है। इस इंस्टीट्यूट से हमारे देश का बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको ठीक से बताया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि वह इंस्टीट्यूट बिहार में बनना चाहिए।

मैं आपको एक और चीज़ के लिए पुन: बधाई देना चाहता हूं कि आपने पुलिस पर भी एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है और फॉरेंसिक साइंस पर भी एक यूनिवर्सिटी बनाने

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

की बात की है। आज के समय में यह बहुत जरूरी है। आज पुलिस का जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, वह बदल गया है। अब पुराने तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। आज की तारीख़ में जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको देखते हुए आप फॉरेंसिक साइंस पर भी जो यूनिवर्सिटी बनाने जा रही हैं, इसके लिए भी हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई देते हैं।

इसके साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है, खास तौर पर हमारे जितनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके माध्यम से आप हमारी जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, वहां टेक्नोलॉजी ले जा रहे हैं और उसे पूरा का पूरा डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी स्कीम है। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में हमारे जितने भी संस्थान हैं, चाहे पंचायत हों, पीएचसीज़ हों, पुलिस स्टेशंस हों, आंगनवाड़ी सेंटर्स हों, आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सबको जोड़ने जा रहे हैं और इसके लिए 'भारत नेट' में आपने 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है। इसके लिए मैं हमारी वित्त मंत्री महोदया को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। अब हम सब जान लें कि आगे आने वाला समय कैसा होने वाला है। अब पुराना समय नहीं है। आगे आने वाले समय में artificial intelligence है, Internet of Things है, 3D printing है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपने एक सबसे बड़ी चीज़ की है, जो बहुत ही अच्छी सोच की है, वह यह है कि आपने Qnantum Technology पर भी ध्यान दिया है। बजट में पहली बार Quantum Technology को मिशन बना कर इसके लिए आपने 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे हमारे देश में लोगों के लिए एक पूरा का पूरा नया vista मिलेगा। इसके बाद युवाओं के लिए आपने इतना अच्छा काम किया है, जिसके लिए मैं पुन: आपको बधाई देता हू कि आपने पहली बार Centralized National Recruitment Agency बनाने का फैसला लिया है। जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, उनकी परेशानी क्या होती है? ...(**समय की घंटी**)... उनको परीक्षा देने के लिए जाना होता है, लेकिन उनके घर में पैसे ही नहीं होते हैं। फिर उनको कहां रहना है, इस बात को भी वे नहीं जानते, क्योंकि वहां उनका कोई रिश्तेदार तो है नहीं। जितनी भी ग्रुप 'सी' की सेवाएं होंगी, सबके लिए आप online eligibility test लेंगे और उसी के आधार पर recruitment करेंगे, आपने ऐसी व्यवस्था की है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पहले भी कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं, आज एक बार फिर कह रहा हूं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने ग्रुप 'बी' तक के लिए इंटरव्यू को खत्म कर दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। ग्रुप 'ए' के लिए मैंने कई बार इस बात को उठाया है कि वहां इंटरव्यू में मैक्सिमम और मिनिमम का निर्धारण करिए और इंटरव्यू की प्रोसीडिंग्स को पूरा का पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराइए, जिससे बच्चों को यह न लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधान मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले बच्चों को बता रहे थे कि परीक्षा के समय टेंशन में मत रहिए, उन्होंने यह बहुत अच्छी बात कही। आज हमारे जितने भी बच्चे competitive examinations में बैठते हैं, उन सबके मन में एक ही चिंता रहती हैं, वह है attempts की चिंता। खास तौर

3.00 p.m.

से हमारे जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो क्रीमी लेयर के ऊपर हैं, साथ ही हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनको अभी 10% रिज़र्वेशन मिला है और जो उसमें कवर नहीं हो रहे हैं। यह बात मैंने एक बार पहले भी उठाई थी, आज फिर से कह रहा हूं। खास तौर पर कॉम्पिटीशन में परीक्षा के लिए बैठने वाले बच्चों में किसी प्रकार का तनाव न हो, इसके लिए attempts की संख्या पर रोक को खत्म कर दीजिए। बच्चों की जब इच्छा हो, वे जब भी और जो भी competitive exam देना चाहें, दें। उनको इस बात का अहसास न हो कि चूंकि हम अमुक समाज में पैदा हुए हैं, इसलिए हम परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। चूंकि वह attempt लेगा, इसलिए किसी प्रकार के आरक्षण में उसका कोई दखल नहीं होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसको लेने से पूरे के पूरे कैम्पस में एक अच्छा माहौल बनेगा।

चूंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए एक बार फिर मैं वित्त मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस रास्ते पर आप चली हैं, उसी रास्ते पर चलिए। हिन्दुस्तान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने और पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का हम लोगों का जो सपना है, यह तभी संभव होगा, जब आपकी सोच पॉज़िटिव होगी, जब आपकी सोच में आशा होगी और जब आपको लगेगा कि भविष्य हिन्दुस्तान का है और हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Madam, the Finance Minister's longest speech has not created any confidence to any section of the society.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA) *in the Chair*]

I am disappointed by the Budget. There is nothing concrete in the Budget for agriculture or unemployment or manufacturing, education and health.

The economy is going through slowdown. What is the reason? Will the Government submit a White Paper on that? Instead of merely talking, why don't you submit a White Paper as to why there is this economic slowdown? Demonetisation ruined the economy. I do not know whether you will agree to that or not. The Government should come out openly that they have committed the mistake. Demonetisation has ruined this economy. Tiny, small, medium industries, real estate all have been ruined. GST, the way it was implemented, gave a further blow to the economy. You are creating a new income-tax system--old regime and new regime. I spoke to several office-going people, nobody is happy. The older regime is better. The new regime means they cannot invest. You don't want the people to save. You want them to spend money. But the peoples' mentality is to save for their future. Your new regime is not going to work and the people are not happy. For MNREGA, you have

[Shri T. K. Rangarajan]

reduced the revised estimates from ₹7,000 crores to ₹6,500 crores. So this is not going to help the ordinary people, the village people. In your speech, you said, "This is the Budget to boost their incomes and enhance their purchasing power." I do not know how you are going to boost the common man's income. You are enhancing and boosting only the corporate sector. All sections of the society will suffer, especially, in rural areas, from the low growth of investment in the past seventeen years. GDP has shrunk in every quarter in the financial year. If we want to be the 5 trillion dollar economy, that means 14.4 per cent GDP for the next five years. Please explain, when you will reply, whether we can achieve 14.4 per cent GDP. What is the way you are going to look? The data released by the Centre for Monitoring Indian Economy, CMIE shows that the unemployment in India has risen to 8.3 per cent by October, 2019, the highest in the past 45 years. You had promised in 2014 that two crore jobs will be created. In 2019, you did not mention anything. You have a different agenda- Ram Temple, Kashmir, etc. You have a different agenda. You are not able to create two crore jobs. But I demand unemployment allowance for the four crores, *i.e.,* 8.3 per cent. How do they behave? Where is their capacity to purchase? They are engineers, they are diploma holders, Ph.Ds, plus-two and tenth passed. I demand for unskilled wage for these unfortunate as unemployment allowance. I demand unemployment allowance. It may be new to you. But these unemployed people, engineers, diploma holders, teachers are suffering without any employment. So there should be unemployment allowance, unskilled wage. I did not demand anything more. Let the Government come up. Then they will get some money at least. But you have created a closure of industries. There are no new jobs. The rural market has shrunk because unbranded items are not able to move. You have levied GST for even 'Kadalai Mittai'. The unemployment allowance will give some breathing for the unemployed citizens. I hope this august House will support this. If you say, "Let the unemployed wait till economic development". I am sorry, they will commit suicide. They will not wait for you. When you spoke about agriculture, we are all worried about the Cauvery Delta districts. Karnataka is thereby building new dams. Oil digging is opposed by the farmers. I do not know whether the Government discussed the 16 action points with the State and Agricultural Associations. There are some good points, I agree. The non-banking financial companies are charging about 22 per cent interest. For one acre of land, for cultivation and labour charge, it is not possible for one to pay 22 per cent interest. Then, they ask you to give relief. Food subsidy expenditure, you have decreased by 8.5 per cent; rural development is

also increased by 1.7 per cent. You wanted to finish off the BPCL and LIC. You see, the Life Insurance Corporation of India was founded in 1956 when the Parliament of India passed the Life Insurance of India Act that nationalized the insurance industry in India. Over 245 insurance companies and provident fund societies were merged to create the State-owned Life Insurance Corporation of India. As of 2019, the Life Insurance Corporation of India had total fund of ₹ 28.3 trillion. The total value of sold policies in the year 2018-19 is ₹ 21.4 million; Life Insurance Corporation of India settled 26 million claims in 2018-19. It has 290 million policy holders. The entire policy holders do not agree with your disinvestment policy. The LIC employees had already gone on one day strike. Why do you want to disinvest? They are paying all your five year plans. I have got a lot of data with me. I can tell you that in 1992-97, they had paid ₹ 56, 097 crore. In every Five Year Plan, LIC is paying for the Government. Then, why do you want disinvestment in the LIC? You want to sell the BPCL. I thought that you don't like Pt. Jawaharlal Nehru. Now only I understand that you want to destroy all Jawaharlal Nehru creations, whether it is the LIC or the BPCL. BPCL employees had gone on two days strike. Sir, I request you to reconsider this. Don't disinvest LIC. As regards BPCL, the Minister is already talking with the Russian people. They had a good lunch also. That is what the newspaper says.

Health and education is also not given enough material. Regarding the Scheduled Caste, the population of the SCs is 16.6 per cent of the Indian population, and if the budget for the SCs is allotted according to their population, it should be 5.05 lakh crore rupees. However, the actual budget allocation is mere 83,000 crore rupees, which is staggeringly short of what is due to them.

Similarly, the population of STs in India is 8.6 per cent and their share in budget allocation is just 1.76 per cent. The percentage of allocation for the Scheduled Tribes also is very limited, that is, 1.90. I request you to enhance all these allocations. When the Minister submits his opinion about the judgment, we will ask questions about that. The SCs/STs and OBCs, unless they are protected, unless they are given proper representation in Government departments, things will not change. You cannot see one chairman in any public sector undertaking of the SC/ST/OBC category. Still, these posts are occupied by the other castes. So, I request the Finance Minister, please provide unemployment allowance through this, please enhance the MGNREGA allocation. By doing so, things will improve. Otherwise, you see, industries are closing down; new industries are not coming up; and you have no light for future. With this, I conclude.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Sir, at the outset, I want to say that this Budget is prepared on false premises. All data are falsified data. Only if you have real data, you can prepare a reasonably good Budget which will take India towards growth. This data, based on which this Budget is prepared, is all false data. The problem is, this Government does not want to accept their failures. My question is, any Government, if they want to improve their economy, they should have confidence in the people of the country. Without the cooperation of the people, no Government can achieve the targeted growth because it is the people who are going to help in developing the economy. When you don't give proper data to the people, if you hide it, you are not hiding it from the Opposition parties, you are hiding the data from 130 crore people. They should know what the position is. Only then can they be prepared to help the Government. We will criticise. We are here to criticise. Thirukkural says, *"Idipparai illada emara mannan kedupparila anung kedumu"*. When there is nobody to question or criticise the Government, the Government will fall on its own. There need not be a third party to make it fall. So, we do the criticism. But, the facts should be known to the people of this country. Only then will they cooperate with you because it is their country. It is not merely the country of the people sitting in both the Houses. It is a country of 130 crore people. They should know what the position is. They should know why there is no employment. If you speak of the actual figures of unemployment, at least these people will not wait for the Government to provide employment and they will take to alternative methods so that they too contribute to the economy of the country.

So, the first thing this Government did is to * the people of India with wrong figures or by not releasing figures as accessed by the Governmental agencies, like NSSO. Why do you hide NSSO figures? Why do you say that NSSO has done a mistake? NSSO is working for the Government. It is not working for the Opposition parties. So, the first thing to take note in this Budget is that the basis on which this Budget is made is on false premises, with wrong data, absolutely false data. I don't know how much you are going to achieve by this Budget. You will not achieve anything.

On individual income-tax, it is a tool for garnering the revenue to the country. It is claimed that it is 'to help salaried class individuals!' The funny thing in the Budget is providing a second set of income-tax rules. I quote:–

> "Further, currently the Income Tax Act is riddled with various exemptions and deductions which make compliance by the taxpayer and administration of the

*Expunged as ordered by the Chair.

Income Tax Act by the tax authorities a burdensome process." So, the income-tax is levied to reduce the burden of income-tax payers and officers. Do you levy taxes to help certain people who are working in the Department? You levy taxes for the sake of welfare of the country. You levy taxes for the sake of the welfare of the poor, welfare of farmers. But, you say that it is to relieve the burden of the tax authorities! How have you reduced? By providing two sets of tax payment routes. I cite an example. If I go to a shop to purchase 50 kilograms of rice, the shopkeeper says, 'You buy this rice, it costs ₹10 a kilogram. If you buy this rice, it costs ₹9 a kilogram.' Then what would I do? I will go in for ₹9 a kilogram rice. When I pay ₹450 for the rice, the shopkeeper says, 'You must pay ₹50 for the bag!' That is the real fact about providing two sets of rules! They say that the tax outgo is reduced. Still, I pay the same! Here, the bag is free but the cost of rice is ₹10 a kilogram. That is the difference. That is what the two sets of tax structures are. You should simplify the taxes.

Secondly, you say 'faceless assessment'. How do you know that faceless assessment is a better thing? Without knowing who is paying the tax, how can you collect it? He can even challenge against the tax in an appeal. Without knowing the face, how can you do it? So, the entire Budget is just a propaganda mechanism. This is my tenth year of listening to the Budget Speeches. This is the longest Budget Speech ever made possible. This Budget will definitely not help India in the direction of growth because, the first thing is, you have failed in taking the people into confidence. The second thing is, what is the duty of the Government? The duty of the Government is to create jobs for its citizens. The duty of the Government is to provide health facilities to its citizens. The duty of the Government is to provide education to its citizens. In all these three sectors you have promised many things, but not one thing which the Government, on its own, will do. You had said Public-Private Partnership mode. This House is there to pass a Budget or take money out of the Exchequer. We are burdened by giving permission to private sector also. Why the private sector? Why not this Government? Why can't you do that? We have done it. This country had seen public institutions, educational institutions. This country had seen thousands of medical centres and hospitals. In Tamil Nadu, until 1976, when we were in power, when Kamarajar was there, up to graduation was free. There were no fees. Only after 1976 the subject

*Expunged as ordered by the Chair.

'education' was taken under the Concurrent List. Now education is the costliest thing. It is ₹ one lakhs or ₹ two lakhs.

Until then it was totally free. Why can you not do that? Health, hospitals are free. In Tamil Nadu we have 26 medical colleges funded by the State Government. We did not go for PPP mode. Each district has a medical college. Why can't you do that if you are really interested in the growth of the people, if you are really interested in the welfare of the downtrodden or weaker sections? You say *sabka saath, sabka vikas.* I don't know what is the meaning of that word. You eliminate a large section of the people and you say that, 'we are with everybody. It is for everybody.' I don't understand the meaning. I don't want to go into the figures because most of my hon. colleagues had gone into the figures. I don't want to go into the figures. If I start going into the figures, I still see a bleak future. That much I can say. There is bungling in tax structures, education. This Budget has bungled every sector. The Government does not want to take the responsibility of providing care to the people of India. This Government does not want to take the people of India into confidence. Without the support of the people of India, the 130 crore population of India, you cannot see development in this country. They are the basis. They should support the Government. They had supported. In crisis the people of India had stood with the Government. During Pakistan war — don't think that I am also chanting 'Pakistan', I am just quoting an incident — many people gave their wealth. They gave whatever they had. They gave their gold ornaments. So, people will stand by the Government when the Government is in crisis. There is a real crisis today. Economy is in crisis. It is not only India. You can say that every country is in crisis. I accept that, but no country is hiding the real facts from their citizens, except us. Here, our Government is hiding all the facts. They don't want the facts to be told to the people, revealed to the people. Then how can you get the cooperation of the people? It is impossible. So, with these words, I finally say that this Budget will not take the country in the right direction of development. It is going to further put the economy down. The Government should change. The Government should listen to the voices of the Opposition, voices of the economists, voices of the thinkers. Otherwise, this Budget is going to be a grand failure. Thank you.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir for giving me this opportunity to speak on the Budget.

Against the backdrop of economic slowdown, hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, presented the Budget for the year 2020-21. Our economy needed

a demand stimulus to pull itself out of the current crisis and, therefore, hon. Finance Minister, was expected to announce a big stimulus that could put money in the hands of people to trigger consumption demand. Though the hon. Finance Minister did try to deliver to the expectations of the people, it fell well short of the targets.

Sir, in this Budget, allocation of about ₹ 2.83 lakh crores has been made for the agriculture sector; ₹ 69,000 crores have been provided for the health sector; ₹ 12,300 crores is the total allocation for Swachh Bharat Mission; ₹ 99,300 crores provided for education sector; and, ₹ 27,300 crores for development of industry and commerce. Declaration of National Infrastructure Pipeline worth ₹ 1.03 lakh crores was highlighted by the hon. Finance Minister in her speech. All these announcements or decisions, if implemented in letter and spirit, the Indian economy would not only take upward swing but would be rated as one of the top economies in the world which is the dream of every Indian. However, the ground reality is different from the rosy picture drawn in the Budget.

Sir, will the hon. Finance Minister explain or shed some light on the following points for my understanding and also for the understanding of this House?

The allocation for the NREGA has actually been reduced by ₹ 10,000 crores from last year and is even lower than the Actuals of 2018-19. The total food, fertilizer and petroleum subsidy amount for 2020-21 is reduced by a whopping 24 per cent from the year 2019-20 BE. Going by the BE of 2019-20, there is absolutely no increase in the amount allocated for direct transfer to farmers under PM-KISAN, so is the case for the Mid-Day Meal Scheme and the health insurance scheme, Ayushman Bharat, for the poor.

Sir, weak demand, low industrial output, lack of jobs, falling household savings and rising inflation have brought the economy to a standstill which demands a huge public spending by the Government. Hope the hon. Finance Minister takes concrete steps in this direction to revive the economy.

Sir, my State Maharashtra and city Mumbai have been completely left out of focus in this Budget. Maharashtra has the highest GSDP among all the Indian States and the UTs. Maharashtra contributes around 15 per cent of India's total GDP at the current prices. It is the second most populous State in the country, but hardly gets 5.6 per cent of total share of Union taxes from the Centre. Maharashtra accounts for 38.5 per cent

[Shri Anil Desai]

of the total direct tax collections in India according to data released by the CBDT. According to BE of 2019-20, Maharashtra was to get an amount of ₹ 44,672 crores out of tax devolution from the Centre which has now been reduced to ₹ 36,220 crores as per the RE of 2019-20 and, on top of it, the dues are not yet received as scheduled which has hampered the developmental works in my State. Hon. Chief Minister of Maharashtra, Shri Uddhavji Thackeray, had written a letter to hon. Finance Minister regarding pending dues till October,2019, which amounted to ₹ 15,500 crores in respect of State's tax dues and share of GST. Such delayed payments have been posing major obstacles in carrying out the developmental works in the State.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

Further, out of 17 iconic tourism sites selected by the Government for development, only Ajanta Ellora in Maharashtra figured in the selected list of sites. In fact, historical monuments like forts of Chhatrapati Shivaji Maharaj should have found place in the iconic tourist sites.

Similarly, Mumbai has been sidelined and instead, IFSC which is operationalized in GIFT City of Gujarat, stands to receive more incentives in this Budget, but no mention in the Budget about Mumbai's IFSC. But, there is no mention in the Budget about Mumbai's International Finance Centre.

Sir, the local railway service is the lifeline of Mumbai and its suburbs. Lakhs and lakhs of commuters daily travel by local trains. Therefore, sizeable budgetary outlay was expected in this Budget to enhance and improvise the rail network in the city and suburbs. But, no provision has been made in this regard in the Budget. Thus, Mumbai, the Financial Capital of the country, is left high and dry.

Announcement of disinvestment in LIC has sent shock waves all over the country and has shaken the organized sector and the employees of public sector. The proposal to sell a part of Government's stake in LIC may fetch handsome returns to the Government. But, it will end the sense of security to one and all. The Life Insurance Corporation, the premier institution, will only end up going in the hands of crony capitalists. I would, therefore, urge the hon. Finance Minister to review the proposal of disinvestment in LIC and cancel the same.

On the similar lines, the Government needs to revisit the cases of BPCL and IDBI and take a decision accordingly.

Sir, on the individual taxpayers' front, new simplified income tax regime has been introduced which looks attractive to an extent. However, the taxpayers opting for the new scheme will not get the benefit of standard deductions and exemptions, as it is available in the existing scheme. Also, taxpayers will not get tax benefit for leave travel concession and allowances for income of minors. Similarly, legislators will also not be getting the benefits of deductions that are available as of now. The middle class salary earners will not benefit out of the new scheme, as they stand to lose on certain savings that are available in the existing scheme. I would, therefore, urge the hon. Finance Minister to review the new income tax scheme by allowing the deductions and exemptions that are available in the existing scheme.

With these words, I conclude my speech, Sir.

STATEMENT BY MINISTER

Regarding reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotions

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावरचन्द गहलोत): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी, 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य **बनाम** उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिज़र्वेशन विषय पर फैसला आया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया और न ही भारत सरकार से शपथ-पत्र मांगा गया। उक्त मामला /एस.एल.पी. उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ, जिसने उत्तराखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं करने का निर्णय लिया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2012 में उत्तराखंड में काँग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not called you, please. ...*(Interruptions)*... It will not go on record. ...*(Interruptions)*... Hon. P.L. Puniaji. ...*(Interruptions)*... I have not called anybody else. ...*(Interruptions)*... Only Shri P.L. Puniaji's query will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें यह है कि उस समय उत्तराखंड में कौन सी सरकार थी, लेकिन यह हकीकत है कि आज के दिन जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और यह स्पष्ट रूप से कहा कि